



प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

लखनऊ::दिनांक 11 फरवरी, 2026

विषय- जनपद रायबरेली में पुलिस लाइन चौराहा से मामा चौराहा ओवर ब्रिज जेल रोड तक मार्ग कुल लम्बाई 2.350 कि०मी० का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग में किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं०-6034/183सी(पीडीआर)-ल०वृ०/2025, दिनांक 10.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद रायबरेली के "पुलिस लाइन चौराहा से मामा चौराहा ओवर ब्रिज जेल रोड तक मार्ग" कुल लम्बाई 2.350 कि०मी० के स्वामित्व का हस्तांतरण नगर पालिका परिषद, रायबरेली" से लोक निर्माण विभाग में किये जाने हेतु निर्णय लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013 के प्रस्तर-3(3)(1) के प्राविधानानुसार जनपद रायबरेली के "पुलिस लाइन चौराहा से मामा चौराहा ओवर ब्रिज जेल रोड तक मार्ग" कुल लम्बाई 2.350 कि०मी० के स्वामित्व का हस्तान्तरण नगर पालिका परिषद, रायबरेली से लोक निर्माण विभाग में किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-82/2026/आई/1235109(1)/23-1-26-23-1099/136/2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन। .
3. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।
4. जिलाधिकारी, रायबरेली।
5. मुख्य अभियंता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7. अधिशासी अभियंता, प्रा०ख०, लोक निर्माण विभाग, रायबरेली ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।